GS-2

VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1514)

Name of Candidate	Bharat Jai prakash Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	
Center	online	Date	14/03/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Highlighting the changes introduced by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) Amendment Act, 2021, analyse various issues with the amended Act. (150 words) 10

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (GNCTD) संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए, इस संशोधित अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए।

हाल ही में संसद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (GNCTD) संशोधन अधि., 2021 द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है जिसका उद्देश्य 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना करना है।

प्रमुख परिवर्तन

- दिल्ली सरकार से तात्पर्य, दिल्ली का उपराज्यपाल है।
- → दिल्ली विधानसभा, प्रशासन संबंधी मुद्दों की जाँच हेतु स्वयं को या किसी समिति को सशक्त नहीं कर सकती है।
- → ऐसा कोई मुद्दा जो संयोगवश राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर हो, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है।
- ↳ विधानमंडल के मंत्रीपरिषद द्वारा सामूहिक या सदस्यों द्वारा निर्णय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल की अनुमति आवश्यक।

मुद्दे
- निर्वाचित सरकार की जगह, उप-राज्यपाल की शक्तियों का समर्थन
- केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति
- वर्ष 2018 के SC के निर्णय का उल्लंघन।
- PUCL बाद में SC द्वारा दिये गये निर्णय (जिसमें कार्यपालिका, SC के निर्णय की अवज्ञा नहीं कर सकती है) का उल्लंघन
- संयोगवश शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

दिल्ली सरकार व केन्द्र के मध्य यह मुद्दा, संवैधानिक न होकर राजनैतिक है जिसका समाधान सहकारी संघवाद से ही संभव है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Are there valid arguments for continuing with sedition law in 21st century democratic India? Discuss in light of the debate surrounding it. (150 words) 10

क्या 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए वैध तर्क विद्यमान हैं? इससे संबंधित वाद-विवाद के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत में ipc की धारा - 124(A) राज्य (विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध) के विरुद्ध बोलकर, कृत्य द्वारा उसे हटाने के प्रयासों को देशद्रोह मानती है।

जारी रखने का तर्क

① सरकार को सुरक्षा प्रदान करती है।

② यदि कोर्ट को Contempt पर कार्यवाही का हक है तो सरकार को भी होना चाहिये

③ सरकार को आपात - स्थिति से निपटने में लाभकारी है।

मुद्दे

① दोषसिद्धी दर बहुत कम है।

② International Covenant on civil & political Rights के विरुद्ध है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ औपनिवेशिक शासन के अनुकूल है।

④ UK, Australia जैसे देशों में भी समाप्ति

⑤ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलाधिकारों के विरुद्ध

⑥ भारत में waging war Against India का प्रावधान है।

SC
→ केदारनाथ सिंह case में संवैधानिक माना
→ एक अन्य केस में सिर्फ नारे लगाना देशद्रोह नहीं माना जा सकता है।

हाल ही में विधि आयोग ने भी परामर्श पत्र में पुनः विचार करने का सुझाव दिया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Identify the issues that have contributed to a decline in the performance of Parliamentary Standing Committees. How can these issues be addressed?
(150 words) 10

उन मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्होंने संसदीय स्थायी समितियों के प्रदर्शन में गिरावट में योगदान दिया है। इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

संसदीय समितियां, विधायिका को कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण में मदद करती है इन्हें सदन के आँख-कान भी कहा जाता है।

प्रमुख समितियाँ
- public Account Committee
- Estimates Committee
- Joint Committee

गिरावट हेतु मुद्दे

① विशेषज्ञता का अभाव है क्योंकि सदन में अपराधीकरण बढ़ रहा है। (ADR रिपोर्ट - 43%)
② कोरम पूरा नहीं हो पाता क्योंकि, एक ही सदस्य अनेक समितियों में शामिल है।
③ सरकार द्वारा bills को संसदीय समितियों को भेजा नहीं जा रहा है। (15th - 27%)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) संसदीय समितियों में राजनीतिक विरोध उभरकर सामने आ रहे है।
(राफेल मुद्दे पर)

समाधान

(1) Comm. के काल कार्यकाल में वृद्धि करना।
(2) संसदीय समितियों में विशेषज्ञता को प्रोत्साहन एवं पुनः निर्मित करना।
(3) नियमित बैठकें आयोजित करना।
(4) सरकार द्वारा विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजना।

संसदीय समितियाँ, शक्ति के नियंत्रण एवं संतुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Despite being a non-constitutional body, the Prime Minister's Office (PMO) has wielded immense decision-making power in India. Discuss the advantages and issues associated with it. **(150 words) 10**

एक गैर-संवैधानिक निकाय होने के बावजूद, प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) के पास भारत में निर्णय-निर्माण की व्यापक शक्ति है। इससे संबद्ध लाभों और मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय की वर्तमान समय में व्यापक भूमिका देखी जा रही है जो कि सरकार पर प्रधानमंत्री के नियंत्रण को दर्शाता है।

नोटबंदी का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रीमंडल से चर्चा किये बिना लेना तथा प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीति-क्रियान्वयन की निगरानी वर्तमान में भूमिका दर्शाती है।

संबंधित लाभ

① नीति में व्याप्त विसंगति पर चर्चा तथा बेहतर क्रियान्वयन

② मंत्री की योजना संबंधी जवाबदेही सुनिश्चित।

③ mission mode में लक्ष्य हासिल करने को प्रोत्साहन।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ सिविल सेवा सुधार को प्रोत्साहन (PM-HR Council, मिशन कर्मयोगी)

मुद्दे -

① शक्ति के केन्द्रीकरण को बढ़ावा देता है।

② संबंधित मंत्रालय के साथ मतभेद (वाहन स्क्रैपिंग policy पर PMO - सड़क मंत्रालय में मतभेद)

③ अन्य मंत्रालयों के कार्यकरण में हस्तक्षेप।

④ PM समकक्षों में प्रथम है परंतु PMO के माध्यम से सर्व-शक्तिशाली भी बना है।

PMO को संबंधित मंत्रालयों को नीति - निर्माण एवं निगरानी तक सीमित रहकर व्यापक हस्तक्षेप से बचना चाहिये क्योंकि लोकतांत्रिक शासन को मंत्रीमंडलीय शासन माना जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Discuss the role of data in governance in India. Also, state the various challenges in this regard and suggest remedial measures.

(150 words) 10

भारत में शासन में डेटा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिए एवं उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

वर्तमान दौर में Data is the New oil की धारणा प्रसिद्ध हो रही है। विश्व बैंक ने भी विश्व विकास रिपोर्ट में public intent data के रूप में Data की शासन में भूमिका को दर्शाया है।

शासन में भूमिका

① बेहतर नीति-निर्माण में
② परियोजनाओं की निगरानी एवं feedback के माध्यम से सुधार में।
③ लाभार्थी पहचान तथा लीकेज कम करने में भूमिका
④ शासन में पारदर्शिता बढ़ाकर जवाबदेही सुनिश्चित करने में

प्रमुख चुनौतियाँ —

① डाटा की खराब गुणवत्ता
② डाटा का एकत्रीकरण का अभाव तथा silos में पड़ा होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) डाटा उपयोग हेतु कुशल मानव संसाधन का अभाव।
(4) साइबर सुरक्षा की चुनौती (2020 में 300% वृद्धि - CERT-IN)

उपचारात्मक उपाय

(1) साइबर सुरक्षा नीति, 2013 को प्रतिस्थापित कर नई नीति जारी करना।
(2) डाटा सुरक्षा कानून (EU के GDPR के समान) की जरूरत)
(3) सरकारी निगरानी पर न्यायिक नियंत्रण।
(4) निजता को परिभाषित करना
(5) केन्द्र - राज्य समन्वय को प्रोत्साहन।
(6) B.N. कृष्णा समिति के सुझावों पर चर्चा कर लागू करना।

बढ़ते साइबर स्पेस को देखते हुये भारत को Data सुरक्षा कमीशन के रूप में स्थायी संस्था का निर्माण करना चाहिये।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. With specific examples, elaborate upon the conditions that led to the emergence of a new civil society in urban India in the last few decades. Also, highlight its contribution towards effecting governance and policy changes.
(150 words) 10

विशिष्ट उदाहरणों के साथ, उन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए जिनके कारण पिछले कुछ दशकों में शहरी भारत में एक नए नागरिक समाज का उदय हुआ है। साथ ही, शासन और नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावित करने में इसके योगदान पर प्रकाश डालिए।

भारत में सूचना - प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ती जागरूकता एवं शहरी मध्यवर्ग के उभरने से नए नागरिक समाज का उदय हुआ है। उदा॰ - पर्यावरण समस्या की जागरूकता के कारण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक think - tank एवं NGOs जैसे - council for environment energy and water, पानी foundation आदि का उदय हुआ है।

प्रमुख परिस्थितियाँ

① सूचना, संचार एवं शिक्षा के कारण जागरूकता

② NGT के कारण पर्यावरण जागरूकता

③ दिल्ली में प्रदूषण एवं पराली

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चलाने को लेकर सार्वजनिक बहस ने सिविल समाज को प्रोत्साहित किया है।

(4) वैश्वीकरण ने MNC एवं शत्रु देशों के हितों को प्रोत्साहित करने हेतु, सिविल समाज को बढ़ावा दिया है।

(5) वैश्विक मानवाधिकार, पर्यावरण संगठनों का उदय (Human rights watch)

प्रभावित करने में भूमिका

(1) पर्यावरण प्रभाव आंकलन के नाम पर आर्थिक विकास की दृष्टि पर Infra project को प्रभावित किया है। (IB रिपोर्ट)

(2) Covid के दौरान प्रवासी श्रमिकों, कश्मीर में मानवाधिकारों पर वैश्विक ध्यान आकर्षण।

(3) वकील समूह, teachers Asn. हितो के अनुसार नीति प्रभावित करते है

सिविल समाज की New war front के रूप में बढ़ती भूमिका को देखते हुये FCRA संशोधन द्वारा विनियमित करने का प्रयास किया है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The Gati Shakti mission has the potential to not only address the issue of infrastructure bottlenecks but also streamline the governance processes in the country. Elucidate. (150 words) 10

गति शक्ति मिशन में न केवल अवसंरचना संबंधी बाधाओं का समाधान करने की क्षमता है अपितु देश में शासन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की भी क्षमता विद्यमान है। स्पष्ट कीजिए।

भारत सरकार ने गति शक्ति मिशन के तहत विभिन्न सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण हेतु एकीकृत प्रयासों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है

अवसंरचना बाधाएँ

1. भूमि अधिग्रहण चुनौती
2. सरकारी निवेश की सीमितता
3. विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय न होना।

समाधान (गति- शक्ति)

1. सभी मंत्रालयों के मध्य समन्वय बढ़ाकर, प्रयासों का एकीकरण।
2. कार्यों के दोहराव से बचकर संसाधनों का दक्ष प्रयोग
3. अंतर- मंत्रालयी सहयोग बढ़ाकर दोषारोपण नहीं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ सड़क निर्माण के दौरान ही नाली निर्माण एवं अन्य कार्य, जिससे प्रयासों एवं संसाधनों की बचत होगी।

⑤ पर्यावरण प्रभाव आंकलन हेतु समयबद्ध प्रयास।

⑥ जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण में जनजातीय मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालय साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे।

⑦ इसके तहत प्रत्येक project में सभी भागीदार मंत्रालयों को शामिल करते हुऐ standard operating procedures (SOPs) का निर्माण किया जायेगा।

PM - गतिशक्ति मिशन भारत में NIP, National monetisation pipeline आदि के मध्य समन्वय द्वारा infra विकास को प्रोत्साहित करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Giving an account of the issues faced by workers in the informal sector, discuss whether the recently launched e-Shram portal can help in addressing them. (150 words) 10

अनौपचारिक क्षेत्रक में श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का विवरण देते हुए चर्चा कीजिए कि क्या हाल ही में प्रारंभ ई-श्रम पोर्टल उनका समाधान करने में सहायता कर सकता है।

SBI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में GST एवं विमुद्रीकरण के पश्चात अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ है (53% → 15%)

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को पेंशन, नियमित वेतन एवं विभिन्न सरकारी लाभों की प्राप्ति नहीं होती है

प्रमुख समस्याएँ

① जटिल श्रम कानूनों की चुनौती

② न्यूनतम वेतन मानकों का पालन नहीं किया जाता।

③ सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी।

④ कौशल विकास प्रोत्साहन का अभाव।

⑤ सरकारी प्रोत्साहन एवं योजनाओं के लाभ का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

e- श्रम पोर्टल – श्रम मंत्रालय ने अनौपचारिक श्रमिकों के व्यापक डाटाबेस बनाने तथा उन्हें एक ID प्रदान कर पहचान सुनिश्चित करेगा।

महत्व

① सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ

② skill Developement एवं skill mapping की जा सकती है।

③ न्यूनतम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा।

④ श्रमिक संहिताओं को लागू करने हेतु केन्द्र-राज्य सहयोग

⑤ व्यापार सुगमता एवं कंपनी की लागत में कमी

e- श्रम पोर्टल भारत में प्रवासी श्रमिकों की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Clarifying the significance of the recent developments on the issue of global minimum tax, discuss its prospects and challenges for India.

(150 words) 10

वैश्विक न्यूनतम कर के मुद्दे के संदर्भ में हालिया घटनाक्रमों के महत्व को स्पष्ट करते हुए, भारत के लिए इसकी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

हाल ही में G-7 देशों ने वैश्विक न्यूनतम कर 15% अपनाने हेतु प्रस्ताव रखा है।

महत्व

(1) Base erosion, tax shifting की प्रथा पर नकारात्मक प्रभाव।

(2) विश्व के देशों के मध्य tax प्रतिस्पर्धा समाप्त करने में भूमिका।

(3) MNCs की जवाबदेहिता में वृद्धि होगी।

भारत के लिये संभावना

(1) भारत में निगम कर पहले से ही अधिक है इसलिये कंपनियां BEPS के माध्यम से धन का दुरुपयोग करती है ऐसे में वृद्धि की tax collection

Call us : 8468022022, 9019066066

Visit us : www.visionias.in

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

संभावना रहेगी।

(2) भारत को प्रतिवर्ष BEPS के कारण ~$500mn की हानि।

चुनौतियाँ –

(1) MNCs एवं USA के साथ digital tax का मुद्दा

(2) Data सुरक्षा पर वार्ता नहीं तथा भारत द्वारा Data स्थानीयकरण पर बल।

(3) वैश्विक लेनदेन हेतु SWIFT पर निर्भरता।

(4) पूर्व विवादों पर चर्चा का अभाव।

global minimum corporate tax निश्चित ही वैश्विक economy के एकीकरण द्वारा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Announcement of the AUKUS security pact heralds a new era of global geo-politics. Comment. Also, discuss how it may affect India's interests.

(150 words) 10

AUKUS सुरक्षा समझौते की घोषणा ने वैश्विक भू-राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, चर्चा कीजिए कि यह भारत के हितों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

हाल ही में USA, UK एवं आस्ट्रेलिया ने एशिया - प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन तथा चीन पर दबाव बनाने हेतु AUKUS नाम से सैन्य संगठन की स्थापना की है।

भू-राजनीति में युग-परिवर्तनकारी -

① पश्चिमी देशों की चीन के संभावी खतरे से निपटने हेतु व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

② दक्षिण चीन सागर में छोटे देशों की सहायता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

③ आस्ट्रेलिया का सैन्यकरण, इस क्षेत्र में नये 'सैन्यीकरण की होड़' को प्रोत्साहित करता है।

④ N. Korea को भी संभावी कदम उठाने हेतु उत्प्रेरित कर सकता है।

⑤ Quad के प्रति अमेरिका व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आस्ट्रेलिया की नीति को प्रभावित करता है।

(6) जापान व S. Korea को भी इस रेस में शामिल होने हेतु प्रभावित करता है।

भारत पर प्रभाव

(1) भारत को भी Nuclear submarine विकास हेतु प्रोत्साहन

(2) हिन्द-सागर क्षेत्र में Net security provider के रूप में AUKUS व Australia से चुनौती

(3) QUAD का महत्व कम कर सकता है।

(4) Quad, USA पर अधिक निर्भरता हेतु एक संकेत के रूप में कार्य करता है।

AUKUS, चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने तथा 'free of Navigation' की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

Visit us : www.visionias.in
Call us : 8468022022, 9019066066

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Effective devolution of finances is an important requirement for Panchayati Raj Institutions (PRIs) to fulfill their objectives. Discuss while also elaborating on the reasons behind lack of financial resources for PRIs in India. (250 words) 15

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रभावी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। भारत में PRIs के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हेतु उत्तरदायी कारणों का वर्णन करते हुए चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान के भाग -4 में वर्णित नीति निदेशक तत्वों के Art-40, स्थानीय स्वशासन की स्थापना हेतु निर्देश देते हैं जिसकी पालना करते हुये 73th एवं 74th संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना समनुषंगिता के सिद्धांत को धरातल पर लागू करने के लिये हुयी। परंतु वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह चुनौतीपूर्ण रहा है।

विन्त के हस्तांतरण हेतु प्रावधान

① पंचायतों को सौंपे गये ऐच्छिक विषयों में विन्त का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण भी शामिल है

② राज्य के विन्त का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण हेतु राज्य विन्त

आयोग की स्थापना की गयी है।

समस्या के कारण -

① GST के बाद, राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ी है तथा covid के कारण केन्द्र द्वारा राज्यों को प्रभावी वित्त का हस्तांतरण समय पर नहीं किया जाना।

② स्थानीय निकायों को, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर वित्त या राजस्व जुटाने हेतु शक्ति स्थानांतरण न करना।

③ केन्द्र सरकार द्वारा cess एवं surcharge का भार बढ़ाने के कारण राज्यों को वित्त हस्तांतरण कम हुआ है। (15th F.C. रिपोर्ट)

④ राज्य - वित्त आयोग की अनुसंशा बाध्यकारी न होना।

⑤ कोविड जनित मंदी का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव

समाधान -:-

① राज्य वित्त आयोग की

अनुसंशा राज्य सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिये।

② वित्त के हस्तांतरण के विषय को ऐच्छिक की बजाय अनिवार्य बनाया जाये।

③ स्थानीय निकायों को property tax एवं अन्य करों की स्थानीय स्तर पर वसूली के हेतु अधिकार प्रदान किये जाये।

④ cess एवं surcharge को भी राज्यों के मध्य बांट जाये।

⑤ स्थानीय निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने हेतु स्थानीय लोकपाल की नियुक्ति की जाये (2nd ARC)

वित्त के हस्तांतरण के बिना PRI की क्षमता एवं कार्यप्रणाली दक्षतापूर्वक नहीं होती है। अतः वित्त के स्थानीय साधनों हेतु प्रयास किया जाना चाहिये (2nd ARC)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Judicial activism is a necessary tool to guard against "legislative adventurism and executive excesses". Critically discuss in the context of the doctrine of separation of powers as provided in the Constitution of India. (250 words) 15

"विधायी जोखिम और कार्यकारी अतिक्रमण" से रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता एक आवश्यक उपकरण है। भारत के संविधान में यथा प्रदत्त शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य जब न्यायपालिका एक एक्टिविस्ट की तरह व्यवहार करते हुये, कार्यपालिका एवं विधायिका को आदेश देने लगती है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। भारत में Justice - P.N. भगवती, V.R. कृष्णाअय्यर को इसका श्रेय दिया जाता है।

न्यायिक सक्रियता के लाभ

① समाज के वंचित वर्गों के मूलाधिकारों की रक्षा संभव हुई है।

② न्याय-प्रणाली का लोकतांत्रिकरण हुआ है।

③ अपराधियों के राजनीतिकरण तथा राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृति को कम करने का

प्रयास हुआ है।

④ स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार जैसे अधिकारों को मूलाधिकारों की मान्यता मिली है।

⑤ कार्यपालिका की अक्षमता को दूर करने का प्रयास हुआ है।

न्यायिक सक्रियता एवं शक्ति पृथक्करण :-

① न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका को बाध्यकारी आदेश देने लगी, जिससे शक्ति का पृथक्करण धुंधला सा गया है।

उदा. - प्रकाश सिंह केस में पुलिस सुधार हेतु आदेश देना।

② न्यायिक सक्रियता के कारण PIL का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे न्यायपालिका पर कार्य का दबाव बढ़ा है तथा Pendency में वृद्धि हुई है।

③ न्यायिक आदेश, कार्यपालिका की

वित्तीय एवं प्रशासकीय क्षमता को ध्यान में रखकर नहीं दिये जाते हैं।

(4) यह न्यायिक सर्वोच्चता को जन्म देता है। जो कि संविधान का उल्लंघन है।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के साथ-साथ नियंत्रण एवं संतुलन की भी कल्पना की थी जिसकी पालना करते हुये न्यायपालिका को भी न्यायिक संयम बनाने की आवश्यकता है।

13. The electoral bond scheme is part of what appears to be a growing trend away from transparency and accountability in electoral funding. Critically analyse. (250 words) 15

चुनावी बॉण्ड योजना उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति का भाग है जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही से दूर जाने की प्रतीत होती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

भारत सरकार ने बजट-2017 में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु चुनावी बॉण्ड योजना शामिल की।

प्रमुख प्रावधान

(1) बॉण्ड की खरीददारी निश्चित समय हेतु, निश्चित बैंक की शाखाओं से ही संभव।
(2) bonds, 1000 के गुणांक।
(3) न्यूनतम - 2000, max - No Limit
(4) सभी लेनदेन online बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही होंगे।

इन सभी प्रावधानों के बावजूद चुनावी बॉण्ड स्कीम को पारदर्शिता एवं जवाबदेही से दूर जाने वाली योजना कहा जा रहा है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिसके निम्न कारण है-

① चुनावी बाण्ड संबंधी जानकारियों को RTI के दायरे में न लाना।

② बॉण्ड खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान है जो crony पूँजीवाद को बढ़ावा देता है।

③ चुनावी बॉण्ड, मतदाता के भी के जानने के अधिकार के विरुद्ध है क्योंकि वह यह नहीं जान सकता कि संबंधित दल को कौन व्यक्ति फंड कर रहा है जिससे पर्यावरण -विद, पर्यावरण संबंधी सरकार की भविष्योन्मुखी नीतियों पर थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट उद्योग से प्रभावित होने की संभावना रहती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ चुनावी bonds, राष्ट्रीय दलों के ही अनुकूल है तथा क्षेत्रीय दलों को हतोत्साहित करता है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अधिकतर फंडिंग कैश में ही होती है।

⑤ एक ओर राजनीतिक दलों को RTI के तहत लाने की बात चल रही है ऐसे में unknown फंडिंग, पारदर्शिता एवं जवाबदेहीता से दूर जाने का प्रयास है।

⑥ चुनावी बॉण्ड पर max सीमा न होना, धनबल व बाहुबल को बढ़ावा देता है।

चुनावी bond स्कीम पर SC में पेंडिंग PIL पर मतदाता के हित एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने हेतु SC को जल्द सुनवाई कर निर्णय लेना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The significance of the principle of subsidiarity was well reflected in the management of the COVID-19 pandemic. Analyse. (250 words) 15
कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में बेहतर समनुषंगिता (सब्सिडियरिटी) के सिद्धांत का महत्व रूप से परिलक्षित हुआ है। विश्लेषण कीजिए।

समनुषंगिता के सिद्धांत के अनुसार स्थानीय समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है

Covid-19 के दौरान महत्व

① कोविड के दौरान गांवों में बाहर से आने लोगों की निगरानी एवं testing में भूमिका प्रमुख रही।

② स्थानीय स्तर पर Covid-19 zones के वर्गीकरण में हेतु Data प्रदान करने स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका रही।

③ Covid के दौरान प्रवासी श्रमिकों तक सरकारी पहुँच सुनिश्चित करने तथा विभिन्न सरकारी लाभ पहुँचाने में

स्थानीय निकायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाली।

④ स्थानीय स्तर पर क्वारेंटाइन जोन के प्रबंधन में प्रभावी रूप से कार्य किया जैसे - राजस्थान के भीलवाड़ा में।

⑤ Covid के दौर में उड़ीसा सरकार ने सरपंचों की शक्ति में वृद्धि कर बेहतर एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

⑥ N-E राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद की भूमिका।

⑦ उड़ीसा में गोंड जनजाति जैसी अन्य जनजातियों के Covid संक्रमित होने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभावी उपाय अपनाकर अन्य लोगों की सुभेद्यता कम की है।

(8) बच्चे, वृद्ध, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं काउंसलिंग में स्थानीय निकायों की भूमिका।

(9) आशा वर्कर्स द्वारा Covid-19 मरीजों के अतिरिक्त गर्भवती महिला, बीमार वृद्ध आदि का स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया।

(10) गांवों में सरकारी स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर का प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका रही।

समनुषंगिता का सिद्धांत गांधी के ग्राम-स्वराज की प्राप्ति की दृष्टि से तथा सुशासन हेतु महत्वपूर्ण है।

15. Social media has ushered in greater transparency and accountability in governance. But accountability through social media is no alternative to institutional accountability. Analyse. (250 words) 15
सोशल मीडिया ने शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत की है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जवाबदेही संस्थागत जवाबदेही का विकल्प नहीं है। विश्लेषण कीजिए।

सोशल मीडिया ने e-गवर्नेंस के प्रोत्साहन द्वारा सूचना तक पहुँच सुगम कर पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार किया है जिसका जिक्र नीति-आयोग ने भी सुशासन Index में किया है।

सोशल मीडिया द्वारा जवाबदेही

(1) सोशल मीडिया द्वारा प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार को public domain में फैलने में समय नहीं लगता है।

(2) मनरेगा, PDS जैसी योजनाओं में सरकारी हस्तक्षेप एवं क्रियान्वयन की जानकारी तक आसान पहुँच।

(3) सूचना, संचार एवं शिक्षा द्वारा जागरूकता सृजन

संस्थागत जवाबदेही का विकल्प क्यों नहीं :→

1. सोशल मीडिया, नैतिक दबाव की तरह कार्य करती है।
2. यह एक अप्रभावी तथा अकुशल ऑडिटिंग को प्रोत्साहित करती है।
3. डाय में छेड़छाड़ कर गलत सूचना का प्रचार संभव है।
4. सोशल मीडिया पर सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती तथा सोशल मीडिया का उपयोग प्रसिद्धी के लिये होना
5. सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में साइबर सुरक्षा, डाय सुरक्षा संबंधी जानकारी का अभाव

संस्थागत जवाबदेही हेतु उपाय

1. सामाजिक जवाबदेही कानून

लागू करना।

2. सोशल ऑडिट हेतु social Audit unity की स्थापना (CAG)
3. सिटीजन चार्टर को प्रभावी बनाने हेतु 2nd ARC की अनुशंसाओं की पालना करना।
4. RTI Act की धारा-8 तथा धारा-22 का दुरुपयोग रोकना।
5. e-गवर्नेंस के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि।
6. डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन

सोशल मीडिया के माध्यम से जवाबदेही तय कर पाना मुश्किल है क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनुकूल है तथा भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में मतैक्यता का अभाव, सोशल मीडिया के माध्यम से जवाबदेही पर सीमा लगाता है। अतः संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था ही यह कार्य करनी चाहिये।

16. Although the State has the right incentives and intentions to deliver public services efficiently, its capacity to do so is questionable. Critically discuss in the context of India. (250 words) 15

यद्यपि राज्य के पास सार्वजनिक सेवाओं के कुशलतापूर्वक वितरण हेतु उचित प्रोत्साहन और उद्देश्य विद्यमान हैं, तथापि ऐसा करने की उसकी क्षमता संदिग्ध है। भारत के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान भारत को एक लोक-कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है जो नागरिकों के लिये गरीमामय जीवन जीने के लिये प्रयास करता है। इसलिये सार्वजनिक सेवाओं का वितरण किया जाता है।

उद्देश्य एवं प्रोत्साहन

① भोजन एवं आवास जैसी मूलभूत सुविधा प्रदान करना। (मनरेगा, PM - आवास)

② नागरिकों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक असमानता कम करना।

③ मानव संसाधन विकास द्वारा भविष्य के लिये कुशल श्रमबल तैयार करना।

④ मानव विकास सूचकांक में भारत को उचित स्थान दिलाना।

⑤ लैंगिक असमानता कम करना तथा समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना।

क्षमता संदिग्ध क्यों :-

① देश के विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापक आर्थिक असमानता।

② विविधतापूर्ण भारतीय समाज में लोगों की आवश्यकताएँ भिन्न-2 है।

③ लाभार्थियों हेतु केन्द्रीकृत डाटा का अभाव।

④ लाभार्थियों की पहचान हेतु exclusion एवं inclusion error (मुख्यतः मनरेगा)

⑤ सेवा वितरण में लीकेज।

⑥ स्थानीय संस्थाओं की सेवा वितरण हेतु क्षमता का अभाव।

⑦ शक्तियों का केन्द्र द्वारा केन्द्रीकरण तथा व्यापक प्रयोग

⑧ शहरी - ग्रामीण डिजिटल अंतराल।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान

① स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने हेतु वित्त का विकेन्द्रीकरण करना।

② डिजिटल सेवा वितरण हेतु शहरी - ग्रामीण क्षेत्राल समाप्त करना तथा भारतनेट, PM-वाणी जैसी परियोजनाओं का उचित क्रियान्वयन करना।

③ e-श्रम पोर्टल के समान व्यापक डाटाबेस तैयार करना।

④ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा सेवा-वितरण करना।

⑤ सेवा वितरण में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका में वृद्धी करना।

राज्य के पास कुशलपूर्ण सेवा वितरण को प्रभावी बनाने हेतु डिजिटल समाधान अपनाने की आवश्यकता है जिसके लिये डिजिटल इंडिया का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. The problem of hunger in India does not lie in food production but various other underlying issues. Discuss in the wake of decline in India's ranking in the Global Hunger Index, 2021.

(250 words) 15

भारत में हंगर (भुखमरी) की समस्या खाद्य उत्पादन में नहीं बल्कि अन्य कई अंतर्निहित मुद्दों के कारण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021 में भारत की रैंकिंग में गिरावट के आलोक में चर्चा कीजिए।

कनसर्न वर्ल्डवाइड एवं वेल्ट हंगर-हिल्फे द्वारा जारी Global hunger Index में भारत की रैंक 2019 के 102 से 106 हो गयी है जिसका कारण Covid जनित प्रभाव माना जा रहा है।

भुखमरी हेतु प्रमुख संकेतक
- Child Stunting
- Child wasting
- under-Nourishment
- शिशु मृत्यु दर

भुखमरी के कारण

① खाद्य वितरण प्रणाली में व्याप्त लीकेज, गुणवत्ता तथा लाभार्थी पहचानने की चुनौती जैसी समस्याएँ इसकी प्रभावशीलता को कम कर भुखमरी को बढ़ावा दे रही है।

② खाद्य सुरक्षा कानून, 2013

1514

VISION IAS™

खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित करता है परंतु पोषण सुरक्षा पर मौन है।

③ भारत की खाद्यान्न बास्केट में food grains का बोलबाला है तथा अंडे, हरी सब्जियाँ एवं फलों का सेवन कम ही किया जाता है।

④ भारत में भुखमरी उत्पादन की कमी के बजाय, उत्पादन के पश्चात खाद्यान्न की क्षति के कारण है। भारत में प्रतिवर्ष 2 lakh cr का खाद्यान्न खराब हो जाता है।

⑤ भारत में प्रसंस्करण का निम्न स्तर भी खाद्यान्न भुखमरी का प्रमुख कारण है (US - 65%, भारत - 15%)

⑥ भारत की खाद्य - बास्केट में विविधता का अभाव है

1514

VISION IAS™

जबकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार भिन्न खाद्यान्न प्रणाली होनी चाहिये।

समाधान

① खाद्य - सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना

② खाद्य - प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन।

③ खाद्य - वितरण प्रणाली में DBT का उपयोग द्वारा, लागत कम करना तथा उपभोक्ता को खाद्य - बास्केट की स्वतंत्रता प्रदान करना।

④ वितरण प्रणाली एवं Logistics संबंधी चुनौतियों का समाधान।

भारत को सतत विकास लक्ष्यों SDG-2030 की प्राप्ति हेतु zero hunger (SDG-2) में सुधार द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिये

18. Democratization of primary healthcare is indispensable for fulfilling the objectives of equitable and comprehensive care in India. Discuss. (250 words) 15

भारत में समान और व्यापक देखभाल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लोकतंत्रीकरण अपरिहार्य है। चर्चा कीजिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किसी भी समाज में महत्वपूर्ण होती है जो कि भविष्य के श्रमबल का निर्माण करती है। भारतीय संविधान स्वास्थ्य को मूलाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढाँचा

भारत में त्रि-स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढाँचा है -

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता :-

① भारत की प्रति व्यक्ति आय ($2100) है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं

की प्राप्ति करने में बाधा है।

② भारत में स्वास्थ्य पर जेब खर्च (लगभग 60%) है जो कि दुनिया में सर्वोच्च माना जाता है।

③ भविष्य में कुशल मानव संसाधन विकसित करने तथा जनांनकीय लाभांश का लाभ लेने हेतु आवश्यक है।

④ भारत में वृद्ध-जनों की बढ़ती संख्या, श्रमबल का अत्यधिक अनौपचारीकरण (90%), प्राथमिक स्वास्थ्य के लोकतंत्रीकरण पर बल देता है।

⑤ भारत में संस्थागत प्रसव सुविधा, शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की उचित व्यवस्था जरूरी है। (NFHS के अनुसार)

⑥ विश्व में सर्वाधिक कुपोषित, ठिगनापन, भारतीय बच्चों में देखा गया है जो प्राथमिक स्वास्थ्य के लोकतंत्रीकरण पर बल देता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रयास -

① PM - आयुष्मान भारत योजना के तहत Health & wellness सेंटर्स की स्थापना।

② आयुष चिकित्सा के post-graduates को सर्जरी की अनुमति विशेषज्ञ चिकित्सों की कमी पूरी करेगी।

③ राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM), टेली-मेडिसीन का प्रोत्साहन।

समाधान - ① मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाकर डॉक्टर्स की आपूर्ति।

② मिडिल-क्लास हेतु स्वास्थ्य बीमा (नीति आयोग रिपोर्ट)

③ चीन के समान परंपरागत एवं Allopathy का संयोजन।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लोकतांत्रिकरण भारत की वर्तमान जरूरत पूरी करते हुये भविष्य की क्षमता निर्माण करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. In the context of the evolving discourse on the Indo-Pacific, analyse the factors driving the global shift towards the region. Also, identify India's interests and challenges in this regard. (250 words) 15

हिंद-प्रशांत (इंडो-पसिफिक) पर विकसित हो रहे संवाद के संदर्भ में, इस क्षेत्र की ओर वैश्विक झुकाव को प्रेरित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इस संबंध में भारत के हितों और चुनौतियों की भी पहचान कीजिए।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान समय में अपनी आर्थिक एवं रणनीतिक स्थिति के कारण वैश्विक शक्तियों का प्ले-ग्राउंड के रूप में उभर रहा है।

प्रमुख कारक

① आर्थिक कारक

↳ चीन का वैश्विक सप्लाई चैन में 12% हिस्सेदारी

↳ वैश्विक सप्लाई चैन में दक्षिण एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की बढ़ती भागीदारी

↳ दक्षिण चीन सागर, हिन्द-महासागर में प्राकृतिक संसाधनों जैसे - PMN व जीवाश्म ईंधन की संभावना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) **राजनीतिक व रणनीतिक कारक**

→ चीन की दक्षिण चीन सागर में एकाधिकारपूर्ण नीति
→ वैश्विक नौवहन का मुक्त एवं स्वतंत्र आवागमन हेतु
→ चीन का उदय एवं पश्चिमी देशों की असुरक्षा।
→ भारत- चीन प्रतिस्पर्धा

भारत के हित

① भारत का 90% मात्रा, 68% मूल्य का व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है इसलिये 'freedom of Navigation' जरूरी है।

② भारत तीन ओर से हिन्द महासागर से घिरा है एवं लम्बी तटरेखा तथा A&N द्वीपों तथा लक्षद्वीप की सुरक्षा।

③ हिन्द महासागर क्षेत्र में Net security provider की भूमिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ हिन्द महासागर में poly-metallic Nodules का खनन तथा Deep Ocean mission हेतु सुरक्षा

⑤ SAARC देशों के साथ बेहतर संबंध।

⑥ खाड़ी देशों के साथ व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा

चुनौतियाँ

① चीन की string of pearls नीति
② मालदीव, श्रीलंका में बढ़ता चीनी प्रभाव
③ चीन की debt trape policy
④ Quad के कारण चीन की भारत विरोधी नीति
⑤ AUKUS के माध्यम से सैन्य-प्रतिस्पर्धा की चुनौती

भारत को व्यवहारिक रूप में चीन के प्रति प्रतिरोध हेतु USA एवं पश्चिमी के साथ संबंध द्वारा संतुलन की नीति अपनानी चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India's Afghanistan policy must be based on a clear-eyed understanding of important strategic goals in the region amidst the current regional and global strategic environment. Elaborate. (250 words) 15
भारत की अफगानिस्तान नीति वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक परिवेश के बीच इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों की स्पष्ट समझ पर आधारित होनी चाहिए। सविस्तार वर्णन कीजिए।

वर्षों लम्बे war on terror के पश्चात नाटो सेनाओं द्वारा 2021 में अफगानिस्तान से वापसी से सत्ता में पुनः तालिबान की वापसी हुई है जिसने न केवल क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है बल्कि, भारत जैसे पड़ोसी देशों के समक्ष कूटनीतिक एवं रणनीतिक चुनौती भी पैदा की है।

भारत के समक्ष विकल्प

① तालिबान से वार्ता –
(a) भारत के लोकतंत्र समर्थन के विरुद्ध
(b) तालिबान को वैश्विक मान्यता नहीं परंतु, अफगान जनता हेतु सामाजिक समस्याओं से निपटने में लाभकारी हो सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन
(a) तालिबान की सत्ता पर वापसी, अतः अव्यवहारिक विकल्प।
(b) तालिबान - पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ायेगा ⇒ आतंकवाद को बढ़ावा संभव।

③ अन्य देशों के समान स्थिति को नजदीक से देखना तथा निर्णय लेना :-
वर्तमान में भारत Just wait and watch की रणनीति का ही पालन कर रहा है तथा अन्य देशों की तरह दोहा में भारत ने भी back-door channel से तालिबान से वार्ता के प्रयास किये है।

भारत की अफगान नीति

① भारत के दृष्टिकोण 'Afgan Led, Afgan owned' पर वैश्विक समर्थन का प्रयास करना।
② अफगानिस्तान में भुखमरी एवं मूलभूत सुविधा सहायता हेतु

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अन्य देशों के साथ सहयोग करना।

③ आतंकवाद से निपटने हेतु USA एवं अन्य Quad देशों के साथ मिलकर लगातार स्थिति की निगरानी रखना।

④ अफगानिस्तान में भारतीय विकास परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

⑤ अफगान शरणार्थियों हेतु क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग।

⑥ Pakistan, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, जिसके लिये सेंट्रल एशिया के देशों एवं पश्चिमी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।

अफगानिस्तान में उपजे मानवता के संकट, सुरक्षित एवं खुशहाल अफगानिस्तान तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान रखते हुये अफगानिस्तान पर भारत को व्यवहारिक रणनीति की जरूरत है।

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in